है जिन्हें अभी तक रोजगार नहीं मिल सका है?

**श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री रामविलास पासवान):** (क) क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम और चल रहे विशेष रोजगार कार्यक्रमों, जैसे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, शिक्षित बेरोजगार युवाओं हेतु स्वःरोजगार योजना, शहरी निर्धनों हेतु स्वरोजगार कार्यक्रम और नेहरू रोजगार योजना से रोजगार कार्यालयों में दर्ज बेरोजगारों सहित बेरोजगार व्यक्तियों के लिए रोजगार अवसर सृजित किये जायेंगे।

(ख) चालू रजिस्टर पर समयावधि के अनुसार पंजीकृत नौकरी चाहने वालों के आकड़े केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रखे जाते हैं, सभी वर्गों के लिए नहीं।

**दालों के मूल्य और उनका आयात**

522. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल: क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या पिछले एक वर्ष के दौरान दालों की बहुत अच्छी फसल होने के बावजूद, इनकी कीमतों में 15 से 20 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है;

(ख) क्या सरकार ने उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर दालों की बिक्री करने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ग) क्या सरकार दालों का आयात करने का विचार रखती है; यदि हां, तो कितनी मात्रा में;

(घ) महाराष्ट्र को कितनी मात्रा में दालें उपलब्ध कराये जाने की सम्भावना है; और

(ङ) दालों के आयात पर कुल कितना खर्च होगा?

**खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल):** (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार दालों का थोक मूल्य सूचकांक एक उप-संवर्ग के रूप में 21.7.1990 और 22.7.1989 को समाप्त सप्ताहों के बीच 10 प्रतिशत बढ़ा।

(ख) नहीं, श्रीमान।

(ग), (घ) और (ङ) दालों का आयात खुले सामान्य लाइसेन्स के अन्तर्गत अधिकृत किया गया है। दालों के आयात करार का रजिस्ट्रेशन नाफेड द्वारा किया जाता है। नाफेड ने 1990-91 वर्ष के लिए (जून, 1990 तक 2.09 लाख मीटरी टन दालों, जिनका मूल्य 132.27 करोड़ रुपये है, का रजिस्ट्रेशन किया है। सरकारी खर्च पर दालों का आयात करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है। इसलिए महाराष्ट्र सरकार को ऐसे आयातित दालों के किसी भाग का आवंटन करने का प्रश्न नहीं उठता।

**Crimes Against SCs/STs**

523. SHRI TALARI MANOHAR: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that more than 14,000 cases of crimes against the scheduled castes and about 3000 cases against scheduled tribes are being registered every year;

(b) whether it is also a fact that the Prime Minister had written a letter to the Chief Ministers to check the atrocities against Scheduled Castes and Scheduled Tribes; and

(c) if so, what are the details thereof and the measures taken by Government to check these atrocities?

THE MINISTER OF LABOUR AND WELFARE (SHRI RAM VILAS PASWAN: (a) The number of incidents of atrocities perpetrated on Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the country during the Years 1988, 1989 and 1990 are as follows:—

| Year | No. of incidents of atrocities perpetrated on | |
|---|---|---|
| | Scheduled Castes | Scheduled Tribes |
| 1988 | 15,207 | 3,364 |
| 1989 | 14,476 | 3,602 |
| 1990 (up to 31.7.90) | 13*(P) | 1,442*(P) |

*Complete data have not been received from some States.

P- Provisional.

(b) and (c) Yes, please. A copy of the letter dated 19.6.90 written by the Prime Minister to all the Chief Ministers